



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2011/श्रावण 3, 1933

No. 164]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2011/SRAVANA 3, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2011

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कुछेक रबड़ रसायनों अर्थात् “एम बी टी एस” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच का अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 15/9/2010-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि

यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, और यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के दिनांक 6 जुलाई, 2005 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/09/2004-डीजीएडी के अनुसारण में 27 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. 87/2005-सी.श. के तहत चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के या वहाँ से निर्यातित कुछेक रबड़ रसायनों (एम बी टी एस) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर मूल रूप से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. और यतः इंडियन मैटल एंड फैरो एलॉयज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में वर्ष 2006 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 16893 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम, की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी ने लागू शुल्क को निरंतर जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने तथा इस बात

की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए निर्णयक समीक्षा जांच शुरू करते हुए 26 जुलाई, 2010 को एक सार्वजनिक सचनाजारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

ख प्रक्रिया

3. वर्तमान जांच में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास को जांच की शुरूआत के बारे में सूचित किया गया था।
- ii. प्राधिकारी ने 26 जुलाई, 2010 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां संबद्ध देश के दूतावास, घरेलू उद्योग, उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी। इस जांच से संबंधित पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावलियों का उत्तर दायर करें और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की प्रतियां इस अनुरोध के साथ ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित संबद्ध देश के दूतावास को भी भेजी गई थी कि वह संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का अनुरोध करें।
- iii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1.	चाइना सनसाइन कैमिकल होल्डिंग लि., चीन जन.गण.
2.	रांगचेंग कैमिकल जनरल फैक्ट्री कं. लि., चीन जन.गण.
3.	शेनयांग नार्थ ईस्ट ऑग्जीलरी कैमिकल इंड कं. लि., चीन जन.गण.
4.	मेयर्स कैमिकल इंक. लि, चीन जन.गण.
5.	लिंकवैल रबड कैमिकल्स कंपनी लि., चीन जन.गण.
6.	पुयांग विलिंग कैमिकल कं. लि.

संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया।

- iv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों, प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1.	जे.के. इंडस्ट्रीज लि., कोलकाता
2.	सिएट लि., मुंबई
3.	अपोलो टायर्स लि., कोच्चि
4.	विरला टायर्स, कोलकाता
5.	एम आर एफ लि., चेन्नई
6.	मैट्रो टायर्स लि., लुधियाना
7.	पोदार टायर्स लि., लुधियाना
8.	रायजन इंड लि., नई दिल्ली
9.	रबड़ प्रोकडक्ट्स लि., थाणे

क्र.सं.	एसोसिएशन का नाम
1.	ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसो. (ए टी एम ए)

v. आयातक प्रश्नावली का उत्तर सिएट लि. तथा अपोलो टायर्स लि. ने प्रस्तुत किया है।

vi. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से जांच अवधि और पूर्ववर्ती 3 वर्षों के लिए आयात के आंकड़े मांगे गए थे जो प्राधिकारी को मिल गए थे।

vii. प्राधिकारी द्वारा 26 जुलाई, 2010 को जारी की गई अधिसूचना के उत्तर में प्राधिकारी को मै. नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इंड लि. (नोसिल) से एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें संबद्ध देश के उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में रबड़ रसायन (एम बी टी एस) के पाटन के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसकी राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, मै. ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसो. (ए टी एम ए) ने इस संबंध में अनुरोध प्रस्तुत किए थे। तथापि, संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है।

viii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा जिसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा।

ix. जैसा कि उल्लेख किया गया है, पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का आवेदन मै. नोसिल से प्राप्त हुआ था जो भारत में संबद्ध वस्तु की प्रमुख उत्पादक है। इसने क्षति विश्लेषण करने के लिए सूचना/आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने हुई क्षति का विश्लेषण करने

तथा भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत निकालने के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना की संभव सीमा तक जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

- x. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 2 मई, 2011 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से विचार व्यक्त करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी प्रदान किया । सार्वजनिक सुनवाई में जिन पक्षकारों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/उत्तरों में दिए गए तर्कों पर इस जांच परिणाम में संगत सीमा तक विचार किया गया है ।
- xi. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2009-31 मार्च, 2010 की है । तथापि क्षति विश्लेषण में अप्रैल, 2006-मार्च 2007, अप्रैल, 2007-मार्च 2008, अप्रैल, 2008-मार्च 2009 की अवधि और जांच अवधि शामिल हैं ।
- xii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा आंकड़ों के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था ।
- xiii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार वर्तमान मामले में प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था । प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पियों की संगत समझी गई सीमा तक प्राधिकारी के जांच परिणाम में विधिवत जांच की गई है ।
- xiv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में जांच की गई थी । संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ।
- xv. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना और तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं ।

xvi. *** यह चिन्ह इस जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का घोतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है।

ग विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

नोसिल के अनुरोध

4. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) मूल जांच और वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद रबड़ रसायन (एम बी टी एस) है। एम बी टी एस का व्यापक रूप से उपयोग विभिन्न रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है। यह एक एक्सीलरेटर है और इसका उपयोग ऑटोमोटिव टायरों, कन्वेयर बैल्टों और फुटवियर उद्योग में भी किया जाता है।
- (ii) प्राधिकारी ने मूल जांच में यह नोट किया कि संबद्ध वस्तु का कोई अनन्य आई टी सी एच एस वर्गीकरण नहीं है और विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम तथा आई टी सी एच एस वर्गीकरण के सीमाशुल्क वर्गीकरण शीर्षों के विभिन्न उपशीर्षों 38.12.10, 38.12.20 तथा 38.12.30 और 29.34.20 एवं 29.25.20 (6 अंकीय स्तर पर) में वर्गीकृत है। तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस उत्पाद को उसके संबंधित व्यापारिक नाम और ऊपर उल्लिखित रासायनिक विवरण के नाम से भी जाना जाता है।
- (iii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की विस्तार से जांच मूल जांच में की थी और यह माना गया है कि आयातित और घरेलू उत्पाद समान वस्तु हैं।
- (iv) वर्तमान समीक्षा जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु और वर्तमान जांच के क्षेत्र के बारे में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी या अनुरोध दायर नहीं किये हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 6. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है। प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/09/2004-डी जी ए डी दिनांक 6 जुलाई, 2005 के तहत जारी अपने अंतिम जांच परिणाम में अन्य बातों के साथ-साथ यह माना है कि विचाराधीन उत्पाद कुछेक विशिष्ट रबड़ रसायन अर्थात् एम बी टी एस है जिसका उपयोग रबड़ उद्योगों के विनिर्माण में किया जाता है। एम बी टी एस का रासायनिक नाम डाईवेंजोथियाजोल डाई सल्फाइड है और इसका अन्य व्यापारिक नाम एक्सीलरेटर

डी एम है। एम बी टी एस का विनिर्माण उचित आक्सीडायजिंग एजेंटों का उपयोग करते हुए एम बी टी के सोडियम लवण के आक्सीडेशन द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग ऑटोमोटिव टायर और ट्यूब उद्योग में किया जाता है और अन्य के साथ-साथ इसका उपयोग कन्वेयर बैलिंग तथा फुटवियर उद्योग में भी होता है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र

घरेलू उद्योग के अनुरोध

7. प्रधिकारी ने वर्तमान जांच स्वतः शुरू की है। देश में नोसिल संबद्ध वस्तु की प्रमुख उत्पादक है। जहां तक अन्य उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन का संबंध है, कोई प्रकाशित सूचना उपलब्ध नहीं है। आवेदक पाटनरोधी नियमों के भीतर आधार संबंधी अपेक्षा की पूर्ति करता है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

8. "घरेलू उद्योग" के अधार के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उपबंध है:-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा।

10. वर्तमान समीक्षा जांच में मै. नोसिल ने जांच शुरूआत संबंधी सूचना का उत्तर दिया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार मै. नोसिल भारत में संबद्ध वस्तु की प्रमुख उत्पादक है। अतः मै. नोसिल पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध वस्तु के "घरेलू उद्योग" की अपेक्षा की पूर्ति करती है।

ड. पाटन का निर्धारण

सामान्य मूल्य

घरेलू उद्योग के अनुरोध

11. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार तर्क दिए हैं:

(i) सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु तरजीही कार्य प्रणाली घरेलू बाजार में बिक्री हेतु संबंधित निर्यातक की बिक्री कीमत है तथापि, ऐसी सूचना केवल संबंधित निर्यातकों के पास ही

उपलब्ध है। इस संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं है। किसी भी हितवद्ध पक्षकार का तर्क यह नहीं है कि घरेलू बाजार में विदेशी उत्पादकों की ऐसी बिक्री कीमत तुरंत उपलब्ध है और याचिकाकर्ता ने उसकी अनदेखी की है। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता से ऐसी सूचना उपलब्ध कराने की आशा की जा सकती है जो याचिकाकर्ता के पास उचित ढंग से उपलब्ध हो। वस्तुतः कई मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने व्यापार पत्रिकाओं में प्रकाशित कीमतों पर विचार किया है। ऐसी कीमतें घरेलू उत्पादकों की कीमतें होनी चाहिए। ऐसी कीमतें सामान्यतः वे कीमतें होती हैं जिन पर निर्यातक देश में खपत हेतु उत्पाद की खरीद की गई है।

- (ii) अतः यह देखा जा सकेगा कि नियमों में "खपत हेतु नियति कीमत" पर जोर दिया गया है और उसे "उस कीमत, जिस पर वस्तु की बिक्री की गई है" से अलग रखा जाना चाहिए। "मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के प्रतिवादी निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान नहीं किया है और चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ मार्जिन हेतु विधिवर्त समायोजित "भारत में संदत्त या संदेय कीमत" के आधार पर परिकलित सामान्य मूल्य के अनुसार किया है। चूंकि वर्तमान आवेदन मौजूदा उपाय की समीक्षा करने के लिए है इसलिए याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वह गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य की गणना के लिए उसी कार्य प्रणाली पर विचार करें।
- (iii) याचिकाकर्ता ने जिस कीमत पर यूरोपीय बाजार में खपत हेतु रबड़ रसायनों की बिक्री की जा रही है, उस कीमत का निर्धारण करने के लिए यूरोप हेतु उसकी निर्यात कीमत अपनाई है।
- (iv) याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि रबड़ रसायन विशिष्टायुक्त रसायन होते हैं और उनका विश्वभर में अत्यंत सीमित बाजार होता है। ये न तो व्यापक रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तु है और न ही इन उत्पादों की कीमतें व्यापार पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित की जाती हैं/उनकी जानकारी रखी जाती है। वस्तुतः विश्व भर में ऐसे बहुत ही कम उत्पादक (संभवतः 10 से कम) हैं, जो ग्राहकों (कम से कम टायर खंड) को उत्पाद की सीधे बिक्री करते हैं। अतः यूरोपीय उत्पादकों ने घरेलू बाजार में जिस कीमत पर उत्पाद की बिक्री की है वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- (v) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और इस बात पर विचार करते हुए कि वास्तविक सूचना विदेशी उत्पादकों के पास है, प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु कीमत के उस साक्ष्य पर विचार करना चाहिए जिस पर यूरोप के घरेलू बाजार में खपत हेतु वस्तु की बिक्री की गई है। ऐसी कार्य प्रणाली न केवल वैधानिक रूप से अनुमत्य है अपितु उचित भी है।
- (vi) ए टी एम ए ने यह सुझाव दिया था कि व्यापार पत्रिका की कीमतों को स्वीकार किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि ऐसी कोई व्यापार पत्रिका नहीं है जिसमें इन उत्पादों की कीमतें सूचित की गई हों। यदि ऐसी कीमतें वस्तुतः उपलब्ध

थीं; तो ए टी एम ए को यह सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान करने से कोई नहीं रोकता है। पाटनरोधी जांचों को एक ऐसी जांच के रूप में नहीं देखा जा सकता जिसमें केवल घरेलू उद्योग सूचना और साक्ष्य प्रदान करेगा तथा अन्य सभी पक्षकारों की भूमिका मात्र उत्तरदाता तक सीमित होगी। यदि ए टी एम ए यह मानती है कि ऐसी सूचना उसके पास तत्काल उपलब्ध है तो ए टी एम ए को संगत सूचना प्रदान करने से कोई नहीं रोकता है।

(vii) प्राधिकारी ने मूल जांच में चीन जन.गण. के निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान न करने के विस्तृत कारण दिए थे। चूंकि किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दावे का खंडन करने के लिए प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है, इसलिए मूल जांच में प्रदत्त व्यवहार पर संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में विचार किया जाना चाहिए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

12. ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आयातकों तथा प्रयोक्ताओं की ओर से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार तर्क दिए हैं :

- (i) संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया डब्ल्यू टी ओ के असंगत हैं और भारतीय नियमों के अनुसार नहीं हैं।
- (ii) अनियम की धारा 9 की व्याख्या अत्यंत भ्रामक है। अनुबंध-1 के पैरा 7 को ही किसी गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु लागू किए जाने की जरूरत होती है। शेनयांग मास्टसुसिता एस. बैटरी कं. लि. बनाम एक्साइड इंड लि. तथा अन्य के मामले में सेस्टेट ने किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पैरा 7 में अनुक्रमणिका निर्धारित की है। वर्तमान मामले में उसे अपनाने की जरूरत है।
- (iii) गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी उचित तीसरे देश में उत्पादन कीमत या लागत के आधार पर किया जाएगा और ऐसा संभव न होने की स्थिति में ही प्राधिकारी कोई अन्य उचित कार्य प्रणाली का सहारा ले सकते हैं।
- (iv) मूल जांच में भी सामान्य मूल्य "आवश्यकतानुसार विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में संदर्भ या संदेय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार" पर आधारित की गई थी। वर्तमान मामले में भी वही कार्यप्रणाली अपनाई जानी चाहिए।
- (v) इ यू के लिए नोसिल की निर्यात कीमत उचित आधार नहीं है और उसका चीन जन.गण. में लागत तथा कीमतों से कोई संबंध नहीं है।

(vi) याचिका और उसके साथ संलग्न अनुबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत की गणना करते समय की गई कटौतियों में असंगतता है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि इसका विस्तार से विश्लेषण किया जाए।

(vii) घरेलू उद्योग ने निर्यात कीमत की गणना में दावा की गई कटौतियों के लिए कोई आधार नहीं दिया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

13. सामान्य मूल्य के बारे में प्राधिकारी ने मामले की जांच निम्नानुसार की है:

- (i) प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच स्वतः आधार पर शुरू की गई थी।
- (ii) तथापि, जहां तक घरेलू उद्योग के अभ्यावेदनों के संदर्भ में एटीएमए के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अन्य के साथ-साथ उस कीमत जिस पर देश के घरेलू बाजारों या उद्गम के देशों में खपत अथवा निर्यात के लिए अभिप्रेत प्रश्नगत उत्पाद की बिक्री की हाती है (या जहां उपयुक्त हो, उस कीमत के संबंधों में जिस पर उद्गम के देश या देशों द्वारा बिक्री अथवा तीसरे देश या देशों को निर्यात किया जाता है तथा उत्पाद के परिकलित मूल्य के संबंध में सूचना) तथा निर्यात कीमतों अथवा जहां उपयुक्त हो उस कीमत के संबंध में सूचना देना अपेक्षित होता है जिस पर आयतक सदस्य के क्षेत्र में किसी स्वतंत्र क्रेता को सर्वप्रथम उत्पाद की पुनःबिक्री की गई है।
- (iii) इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर देकर प्राधिकारी को निष्पक्ष एवं वस्तुपरक जांच परिणाम तक पहुंचने में सहायता देना अपेक्षित होता है। प्राधिकारी ने संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया था। चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में सहयोग नहीं किया है और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के खंडन हेतु कोई सूचना प्रदान नहीं की है इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था का अनुमान अखंडित रहता है। अतः प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निहित अन्य पद्धतियों के बारे में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने "किसी अन्य उचित आधार" की पद्धति अपनाकर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

14. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में किए गए उपबंध के अनुसार अन्य वैकल्पिक पद्धति के बारे में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना न होने के कारण प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, ईस्टतम खपत मानकों तथा परिवर्तन लागत एवं उचित लाभ पर विचार करते हुए चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों/निर्यातकों हेतु सामान्य मूल्य परिकलित किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य *** अम.डॉ./किग्रा. बनता है।

निर्यात कीमत

15. निर्यात कीमत के बारे में प्राधिकारी ने इस मामले की निम्नानुसार जांच की है :

- i. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने न तो जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर दिया है और न ही इस प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना प्रदान की है। निर्यातकों/उत्पादकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर "निर्यात कीमत" निर्धारित करते हैं।
- ii. इस संबंध में, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या संगत अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु आई बी आई एस तथा डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदत्त आयात आंकड़ों का प्रयोग किया जा सकता है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने आई बी आई एस द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर मात्रा, मूल्य और आयात कीमत का दावा किया है। प्राधिकारी ने आई बी आई एस लोत से आयात आंकड़े स्वीकार किए हैं जिनमें डी जी सी आई एंड एस से अधिक आयात की मात्रा सूचित की गई है ताकि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आयात की मात्रा और मूल्य का निर्धारण किया जा सके।
- iii. अतः प्राधिकारी ने आई बी आई एस द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर विचाराधीन उत्पाद की भारित औसत आयात कीमत निर्धारित की है। यह देखा जाता है कि आई बी आई एस में सूचित आयात कीमतें सी आई एफ आधार पर हैं। संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर "निर्यात कीमत" निर्धारित की है।
- iv. तदनुसार निर्यात कीमत की गणना भारित औसत सी आई एफ आधार पर की गई है। निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े और बीमा, पत्तन प्रभारों तथा कमीशन पर किए गए व्यय को घटा दिया गया है। इस पद्धति से निवल निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	इकाई	चीन जन.गण.
आयात मात्रा	मी.ट.	444
आयात मूल्य	लाख रुपए	491.89
सी आई एफ निर्यात कीमत	रु./किग्रा.	109.67
परिवर्तित दर	रु./अम.डॉ.	48.30
सी आई एफ निर्यात कीमत	अम.डॉ./किग्रा.	2.27

कीमत समायोजन (कुल)	अम.डॉ./किग्रा.	***
कारखाना गत निर्यात कीमत	अम.डॉ./किग्रा.	***

पाटन मार्जिन

16. इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना (दोनों कारखाना स्तर पर) के आधार पर संबद्ध देश के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए जांच अधिके के दौरान पाटन मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है :

	इकाई	राशि
परिकलित सामान्य मूल्य	अम.डॉ./किग्रा.	***
निवल निर्यात कीमत	अम.डॉ./किग्रा.	***
पाटन मार्जिन	अम.डॉ./किग्रा.	***
पाटन मार्जिन	% रेंज	10-20

च. पाटन जारी रहना या उसकी पुनरायुक्ति होना:

17. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार तर्क दिए हैं:

- वर्तमान मामले में संबद्ध देश से निर्यात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में निर्यातक पाटित कीमत पर संबद्ध वस्तु का निर्यात जारी रखेंगे ।
- वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और पर्याप्त है । यह स्थिति तब है जब पाटनरोधी शुल्क विद्यमान हैं ।
- पूर्व में संपन्न की गई जांच में भी प्राधिकारी ने अत्यधिक पाटन मार्जिन पाया था और जांच का समापन संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाकर किया था । पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश से पाटन अत्यधिक बना हुआ है ।
- संबद्ध देश के निर्यातक/उत्पादक द्वारा तीसरे देशों को किए गए संबद्ध वस्तु के निर्यात भी पाटित कीमत पर किए गए हैं ।
- पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में कीमतें विदेशी उत्पादकों के लिए निर्यात करने हेतु काफी आकर्षक हैं । पाटनरोधी शुल्क के वर्तमान स्तर पर भी कीमत

कटौती अत्यधिक सकारात्मक है। याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती की गणना की है जो अत्यधिक सकारात्मक बनती है जिससे यह पता चलता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त या वापस लिए जाने की स्थिति में विदेशी उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता और बढ़ जाएगी जिसके परिणामस्वरूप पाटित कीमतों पर आयातों में आगे और वृद्धि होगी।

- vi. चीन जन.गण. में क्षमता के साथ मांग पर विचार करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन जन.गण. में मांग की तुलना में अत्यधिक बेशी क्षमता है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इन निर्यातकों द्वारा भारत में बड़े और उभरते हुए बाजार को पाटित निर्यातों की अत्यधिक मात्रा भेजे जाने की संभावना है जिससे पाटन जारी रहने की संभावना है। बेशी क्षमताओं से संबंधित साक्ष्य दायर किए गए अनुरोधों के साथ-साथ उपलब्ध कराए गए हैं।
- vii. शुल्क समाप्त किए जाने या वापस लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा होगा और घरेलू उद्योग कीमतों की बराबरी करने के लिए बाध्य होगा।
- viii. विदेशी उत्पादकों ने असहयोग को तरजीह दी है और इसलिए प्राधिकारी को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना को अपनाना चाहिए।

ए टी एम ए द्वारा किए गए अनुरोध

18. ए टी एम ए ने यह तर्क दिया है कि पाटन और क्षति जारी रहने का कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए निर्णयक समीक्षा जांच समाप्त की जानी चाहिए। उसने आगे यह तर्क दिया है कि:

- i. घरेलू उद्योग की गोपनीयता का दावा अवांछित है।
- ii. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत उल्लिखित (संभावना) शब्द के उपयोग से ये संकेत मिलता है कि किसी सकारात्मक संभावना का निर्धारण तभी किया जा सकता है जब साक्ष्य से यह पता चले कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना है न कि मात्र इस वजह से कि साक्ष्य से यह संकेत मिलता है कि ऐसा कोई परिणाम संभावित या आसनन्वर्ती हो सकता है। विनाती आर्गेनिक्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट ने यह निर्णय दिया है कि प्राधिकारी को जिस बिन्दु पर विचार करना अपेक्षित है उसे कुछेक सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए न कि मात्र कल्पना और अनुमानों पर।
- iii. निर्णयक समीक्षा जांच में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अनुबंध-II में निर्धारित मापदंडों के आधार पर घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण करना अपेक्षित होता है। यदि विभिन्न क्षति मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है तो प्राधिकारी शुल्क को वापस ले सकते हैं।

iv. घरेलू उद्योग ने याचिका में पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारेमें अपुष्टिकृत दावे किए हैं ।

v. घरेलू उद्योग के सुधरे हुए निष्पादन को देखते हुए पाटन की संभावना का तर्क अवांछित है ।

vi. पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति को भारत में हो रहे आयातों पर आधारित होना चाहिए और उसे तीसरे देशों को हुए निर्यातों पर आधारित नहीं किया जा सकता । प्राधिकारी नोसिल द्वारा ई यू को किए गए संबद्ध वस्तु के निर्यात की कीमत पर संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य आधारित नहीं कर सकते ।

vii. संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमताओं के बारे में घरेलू उद्योग ने आधारहीन दावे किए हैं । बेशी क्षमताओं का दावा अपुष्टिकृत है । मात्र बेशी क्षमता से वास्तविक क्षति के खतरे का आधार तैयार नहीं होता है । इंडियन स्पिनर एसो. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने स्पष्टतः यह निर्णय दिया गया है कि बेशी उत्पादन क्षमता की मौजूदगी को क्षति के स्पष्टतः दृष्टव्य एवं आसनवर्ती खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई है । प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के एम बी टी एस के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है और निर्धारित प्रपत्र में तथा ढंग से सूचना प्रदान नहीं की है । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आई बी आई एस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचीना से जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण. से एम बी टी एस के 444 मी.ट. के आयातों का पता चलता है । यह भी नोट किया जाता है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन है । प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में चीन जन.गण. से एम बी टी एस के आयात जारी रहने की संभावना है जिसकी वजह यह है कि संबद्ध देश के पास इस प्रकटन विवरण में जिस साक्ष्य पर बाद में कार्रवाई की गई है उसके अनुसार संबद्ध वस्तु के उत्पादन की अत्यधिक बेशी क्षमताएं हैं ।

छ. क्षति

घरेलू उद्योग के विचार

21. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद का आयात जारी है। वस्तुतः मात्रा में वर्षानुवर्ष समग्र रूप में वृद्धि हुई है। मीजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयात मात्रा काफी अधिक बनी हुई है। इसके अलावा, आयात की मात्रा पूर्ववर्ती जांच के दौरान सत्यापित आयातों की मात्रा से काफी अधिक है। यह मात्रा पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने से पूर्व की मात्रा से अधिक है। इससे संभावना की स्पष्ट पुष्टि होती है।
- ii. पाठित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि जारी है और घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है। चूंकि पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी आयात सस्ते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं ने आयातों का सहारा लिया है। इन आयातों का कोई अन्य कारण नहीं है।
- iii. जहां तक आयतकों के इस दावे का संबंध है, कि बेल्जियम से हुए आयातों में वृद्धि हुई है, यह अनुरोध किया जाता है कि चीन जन.गण. से आयात कीमत की तुलना में बेल्जियम से आयात कीमत काफी अधिक है।
- iv. आयात कीमत उस कीमत का द्योतक है, जिस पर संबद्ध वस्तु का भारत में आयात किया गया है, परंतु यह उस कीमत का द्योतक नहीं है जिस पर उपभोक्ता उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि इन वस्तुओं का आयात रबड़, रसायन विनिर्माताओं द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इनकी पुनः बिक्री कीमत उस कीमत से काफी अधिक है जिस कीमत पर वस्तु का आयात किया गया है। इन आयातों में घरेलू उद्योग के समक्ष प्रतिस्पर्धा आयातित उत्पाद की पुनः बिक्री कीमत से होती है। ऐसी पुनः बिक्री कीमत काफी अधिक होने के कारण तीसरे देशों से आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूलभूत कारण नहीं है।
- v. आयातों की पहुंच कीमत विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत से कम है। पहुंच कीमत पर वर्ष 2007-08 में तेजी से गिरावट आई जबकि लागत में वृद्धि हुई। परिणामतः घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि होने के बावजूद कीमत को कम करने के लिए बाध्य हुआ। घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों में की गई इस कमी के बावजूद आयात मात्रा में वृद्धि हुई।

vi. वर्ष 2008-09 में बाजार मंदी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। वर्ष 2009-10 में बाजारों के मंदी से उबरने और निविष्टि लागत में गिरावट आने के कारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने भी अपनी कीमतें घटा दीं। तथापि, आयात कीमतों में और भी अधिक गिरावट आई। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा कीमतें घटाने के बाद भी आयात कीमतों में गिरावट बिक्री कीमत में की गई गिरावट से अधिक रही थी। परिणामतः आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई।

vii. याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि गोपनीयता के दावे तथ्यतः और विधितः दोनों के मद्देनजर अपेक्षित होते हैं। उन सभी चल रही जांचों में जिनमें रबड़ रसायनों पर विचार किया जा रहा है, याचिकाकर्ता ने गोपनीय मानी गई ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं किया है। उद्योग जगत में ऐसी ही परंपरा रही है जिसमें कोई भी प्रतिस्पर्धी बाजार में कोई सूचना का प्रकटन नहीं करता है और उसे व्यापार संवेदनशील सूचना मानता है और उद्योग जगत एक निकटवर्ती व्यापारिक उद्योग है। ऐसी सूचना के प्रकटन से उसके बाजार में बाधा आ सकती है क्योंकि ग्राहक इन साधनों का लाभ लेगा और कंपनी को कीमतें कम करने के लिए विवश करेगा।

viii. विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर कटौती हो रही है।

ix. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद उत्पादकों और निर्यातकों की क्षमता का अत्यधिक बाजार हिस्सा बना हुआ है जिससे स्पष्टतः यह पता चलता है कि वर्तमान शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में उपभोक्ता संबद्ध देश से आयात में वृद्धि करेंगे।

x. पर्याप्त सकारात्मक कटौती से यह संकेत मिलता है कि पाटनरोधी शुलक समाप्त किए जाने पर संबद्ध वस्तु के बाजार हिस्से में वृद्धि होगी। पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती काफी अधिक है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग कीमतों में अत्यधिक कमी करने के लिए बाध्य होगा।

xi. चीन के उत्पादकों ने लागू शुल्क को आमेलित कर पाटन की मात्रा में वृद्धि की है। उपभोक्ता पाटनरोधी शुल्क छूट स्कीमों के भुगतान से छूट को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना इन उत्पादों का आयात कर सकते हैं।

xii. मांग में वृद्धि होने के बावजूद जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग वर्तमान और संभावित मांग के मद्देनजर क्षमताएं बढ़ाता है लेकिन घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ है।

xiii. शुल्क लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग के लाभ में वृद्धि हुई जिसमें बिक्री मात्रा में गिरावट आने के कारण पुनः कमी हुई। ब्याज एवं मूल्यहास पूर्व लाभ में भी वर्तमान क्षति अवधि में गिरावट आई है।

xiv. हालांकि, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट नहीं आई है। तथापि, ऐसा पाठनरोधी शुल्क लागू होने के कारण हुआ है। यदि बाजार में पाटित आयात न हुए होते तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में आगे और सुधार हो सकता था। इसके अलावा, पाटित आयातों की सतत मौजूदगी के मद्देनजर निष्पादन ईष्टतम से कम रहा है।

xv. जहां तक जांच अवधि को बढ़ाए जाने के बारे में एसोसिएशन के तर्क का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने जांच अवधि बढ़ाने की मांग नहीं की है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ पूर्ववर्ती वर्षों के साथ वर्तमान जांच अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार किया है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए निर्णायक समीक्षा के समय वास्तविक निष्पादन और उसकी संभावना, दोनों का निर्धारण करना अपेक्षित होता है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए 4 वर्ष की अवधि का निष्पादन प्रासारिक होता है जबकि क्षति के निर्धारण हेतु अपेक्षाकृत अधिक अवधि आवश्यक होती है जिससे कि क्षति की संभावना का निर्धारण किया जा सके।

xvi. वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह मानने पर कि घरेलू उद्योग को सतत क्षति नहीं हो रही है, निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया क्षति की संभावना की जांच करें।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

22. ए टी एम ए द्वारा संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं और प्रयोक्ताओं की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं। वर्तमान मामले में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है:

- क्षति अवधि को बढ़ाने के बारे में घरेलू उद्योग के दावे की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि बढ़ाई गई अवधि कानून और निर्दिष्ट प्राधिकारी की नियमित पद्धति के विरुद्ध है; पिछले कई मामलों में केवल 4 वर्ष की अवधि पर विचार किया गया है। जब जांच

शुरूआत संबंधी अधिसूचना केवल 4 वर्ष से संबंधित होती है तो इस संबंध में आगे कोई जांच नहीं की जा सकती ।

- (ii) अन्य देशों से हुए आयात संबद्ध देश से हुए आयातों से काफी अधिक है । अतः घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री अथवा बाजार हिस्से में आई किसी गिरावट का कारण संबद्ध देश से हुए आयात नहीं माना जा सकता । अन्य देशों खासकर बेल्जियम से हुए आयातों ने अत्यधिक बाजार हिस्सा हासिल किया है ।
- (iii) संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है ।
- (iv) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है । उसने नए निवेश भी किए हैं । अतः यह जरूरी है कि घरेलू उद्योग का लाभ कम होगा क्योंकि लाभों का उपयोग नए निवेशों का उपयोग प्रचालन लागत की वसूली के लिए किया गया है ।
- (v) रोजगार और वेतन के आंकड़ों से भी लाभ से संबंधित अन्य आंकड़ों का समर्थन मिलता है जिनसे पाटनरोधी शुल्क की अवधि के दौरान निरंतर और बेहतर वृद्धि का पता चलता है ।
- (vi) घरेलू उद्योग ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि मालसूची के स्तर में गिरावट आई है । इसके अलावा, मालसूची के कम स्तर से शुल्क जारी रहने के संबंध में घरेलू उद्योग के मामले को समर्थन नहीं मिलता है ।
- (vii) इसके अलावा, लगाई गई पूंजी पर आय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान निवेश पर बेहतर आय प्राप्त करने में समर्थ रहा है ।

(viii) घरेलू उद्योग की कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है क्योंकि आयातों के सी आई एफ मूल्य में पाटनरोधी शुल्क लागू रहने की अवधि के दौरान या तो वृद्धि हुई है या वह एक समान रहा है ।

(ix) घरेलू उद्योग की कीमत में कोई ह्रास और न्यूनीकरण नहीं हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में समर्थ है और आयातों के पहुंच कीमत तथा सी आई एफ मूल्य में भी जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है ।

(x) विभिन्न मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में हुए सुधार को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी को क्षति के बारे में घरेलू उद्योग के दावों को निरस्त कर दिया जाना चाहिए ।

(xi) जांच अवधि को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आई है। मांग में वृद्धि न होने से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चलता है ।

(xii) घरेलू उद्योग के संबद्ध उत्पाद की निर्यात बिक्री में अत्यधिक गिरावट आई है ।

(xiii) घरेलू उद्योग को हुई क्षति और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है ।

(xiv) घरेलू उद्योग द्वारा आधार वर्ष का परिवर्तन भ्रामक है - निर्णायक समीक्षा शुय करने के लिए डी जी ए डी द्वारा जारी सं.15/14/2009-डीजीएडी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 शामिल होंगे जिसमें वर्ष 2006-07 को आधार वर्ष माना गया है । तथापि, घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण हेतु माननीय नि. प्रा. द्वारा अपेक्षाकृत अधिक क्षति क्षति अवधि पर विचार करना चाहिए । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय नि. प्रा. ने अपनी परंपरानुसार अधिसूचना में दी गई

अवधि से अधिक की क्षति अवधि की अनुमति नहीं दी है और इसका विरोध भी जांच की शुरुआत के समय घ. उ. ने नहीं किया है, इसलिए घ. उ. के तर्क को निरस्त किया जाना चाहिए।

हितबद्ध पक्षकारों के प्रकटन विवरण के बाद अनुरोध

23. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण के बाद निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन अत्यधिक समारात्मक रहा है और चीन जन. गण. से हुए आयातों पर घरेलू उद्योग की कीमत या मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ii) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट अन्य देशों से हुए आयातों के बाजार हिस्से तथा अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में हुई वृद्धि के कारण आई है। चीन जन. गण. से हुए आयातों के बाजार हिस्से के साथ इससे भी चीन जन. गण. से हुए आयातों और घरेलू उद्योग के आयातों में गिरावट के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं होता है।
- iii) घरेलू उद्योग पर मात्रात्मक प्रभाव चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयात के कारण नहीं पड़ा है अपितु तीसरे देशों से हुए आयातों में वृद्धि के कारण पड़ा है।
- iv) यद्यपि संबद्ध आयातों का कीमत कटौती और कीमत हासकारी प्रभाव पड़ा है तथापि जैसा कि स्वयं प्राधिकारी ने माना है जांच अवधि में घरेलू उद्योग पर कोई कीमत हासकारी/न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ा है।
- v) जांच अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ और निवल बिक्री प्राप्ति दोनों में वृद्धि हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि आरोपित कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री का घरेलू उद्योग की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और वह निवल बिक्री प्राप्ति तथा बिक्री लाभ को बढ़ाने में सक्षम रहा है।
- vi) बेल्जियम से हुए आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और बेल्जियम से पहुँच कीमत के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हुई है।

vii) बेल्जियम से हुए आयातों के कारण अत्यधिक कटौती को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी को बेल्जियम से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण करना चाहिए और उसे चीन जन. गण. से हुए आयातों की वजह नहीं मानी जानी चाहिए ।

viii) डीजीएडी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह में गिरावट आई है । तथापि यह स्थापित क्षमता में वृद्धि हेतु किए गए निवेशों के कारण हो सकती है । डीजीएडी को सही स्थिति का पता लगाना चाहिए ।

ix) घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त क्षमता के आंकड़े अप्रासंगिक हैं क्योंकि इनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । यह बात निश्चित नहीं है कि इन उत्पादों का निर्यात भारत को होगा ।

x) जहाँ तक क्षतिरहित कीमत का संबंध है, यह बताया गया है कि लगाई गई पूंजी पर 22% के उचित लाभ (कर-पूर्व) की अनुमति प्राधिकारी ने दी थी । ऐसा कोई अनुमान गलत है कि घरेलू उद्योग को लगाई गई पूंजी पर प्रतिवर्ष आय निश्चित करनी चाहिए ।

xi) परिकलित सामान्य मूल्य के लिए विचारित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं ।

xii) घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि सामान्य मूल्य अर्थात् उस कीमत का निर्धारण करने के लिए जिस कीमत पर खड़ रसायन यूरोपीय बाजार में खपत हेतु बेचे जा रहे हैं, यूरोप हेतु घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत अपनाना उचित रहता जैसा कि पीएक्स-13 के मामले में किया गया था ।

xiii) पाटन एवं क्षति की संभावना के बारे में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश से आयात पाटित कीमत पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु का पाटन निर्यातकों द्वारा जारी रहेगा ।

xiv) इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा पुष्टिकृत अत्यधिक पाटन मार्जिन और चीन में माँग की तुलना में भारी बेशी क्षमता को ध्यान में रखते हुए भारत में बड़ी मात्रा में प्राटित निर्यात भेजे जाने की संभावना है ।

xv) यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जाता है और घरेलू उद्योग आयातों की पहुँच कीमत के बराबर कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य होता है तो घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा होगा ।

xvi) घरेलू उद्योग ने लिखित अनुशेषों और उत्तरों में पर्याप्त साक्ष्य प्रदान कर पाटन एवं क्षति की संभावना की पुष्टि की है ।

xvii) घरेलू उद्योग के कुछेक क्षति मापदण्डों में सुधार होने से लागू पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का पता चलता है । तथापि, संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है और संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है ।

xviii) बेल्जियम से आयात अत्यधिक उच्च कीमत पर हो रहे हैं और ये आयात भारत में ऐसे अन्य रबड़-रसायनों के उत्पादकों द्वारा किए जा रहे हैं जो बाजार में इनकी पुनः बिक्री कर रहे हैं । इन उत्पादकों की पुनः बिक्री कीमत आयात कीमत से काफी अधिक हैं । व्यापार स्तर अलग-अलग है । सीआईएफ या पहुँच कीमत प्रत्यक्षतः तुलनीय नहीं है ।

xix) घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत काफी कम है जिसकी समीक्षा की जाए ।

xx) घरेलू उद्योग को संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा लागू पाटनरोधी शुल्क समायोजित करने की पुष्टि हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है । यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो निर्यातक पाटन की मात्रा में वृद्धि करेंगे ।

xxi) इसके अलावा, निर्यातकों के पास अत्यधिक बेशी क्षमताएँ हैं जिन्हें वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में भेज दिया जाएगा ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने क्षति से संबंधित मुद्दे की निम्नानुसार जांच की है:

- (i) प्राधिकारी नोट करते हैं कि पा. रो. नियमावली में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण हुई क्षति के निवारण हेतु प्रयोक्ता उद्योग की मांग की पूर्ति करनी चाहिए ।

(ii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने क्षति अवधि के दौरान क्षति संबंधी आंकड़ों की जांच और मूल्यांकन करने के लिए सुसंगत परंपरा का पालन किया है। तथापि, निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी यह निर्धारण करते हैं कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने से पाठन और परिणामी क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।

(iii) प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर अत्यधिक कीमत कटौतीकारी और कम कीमत पर बिक्रीकारी प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग को कुछेक मापदण्डों के संबंध में भी क्षति हुई है यद्यपि उसने लाभप्रदता और निवल बिक्री कीमत जैसे कुछेक अन्य मापदण्डों के बारे में सकारात्मक निष्पादन दर्ज किया है।

(iv) उपर्युक्त परिदृश्य तब बना है जब संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग की स्थिति के बारे में इसी परिदृश्य पर विचार किया है। निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में कानून में किए गए प्रावधान के अनुसार इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने पाठन एवं क्षति के संबंध में संभावना का विश्लेषण किया है।

(v) प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा के मामले में प्राधिकारी द्वारा कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार अपनाया जाने वाला उचित मापदण्ड यह है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाठन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में पाठन एवं क्षति की संभावना के पहलू पर विचार किया है।

(vi) इस संबंध में प्राधिकारी ने यह पाया है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद जारी हैं। अतः शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होगी। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध आयातों का अत्यधिक कीमत कटौतीकारी और कम कीमत पर बिक्रीकारी प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि जहाँ तक संबद्ध वस्तु का संबंध है, संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के पास व्यापक वेशी क्षमताएँ हैं जिन्हें पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में भेजे जाने की संभावना है।

(vii) उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाठन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(viii) जहाँ तक घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत के बारे में उठाए गए मुद्दों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसका निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।

(ix) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदण्डों की तथ्यप्रक जांच की है।

(x) जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

(xi) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव ; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

(xii) वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभाव तथा कीमत और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति की मौजूदगी और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की जांच की जा सके।

मात्रात्मक प्रभाव

मांग का निर्धारण

25. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग के निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों में जोड़ा गया है जिसका सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	438	498	314	444
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	72	101
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	15	15	214	373
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	1445	2514
कुल आयात	मी.ट.	453	513	529	817
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	117	180
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	870	761	704	809

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	81	93
अन्य भारती उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	406	375	374	438
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	92	108
कुल मांग	मी.ट.	1,729	1,650	1,607	2,065
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	93	119

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है और उसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मांग में लगभग 19% की वृद्धि हुई थी।

आयात मात्रा तथा बाजार हिस्सा

27. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (ii) में प्रावधान है कि "पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष अत्यधिक वृद्धि हुई है". इस प्रकार, जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

28. निम्नलिखित तालिका से आयात मात्रा और बाजार हिस्से से संबंधित स्थिति का पता चलता है -

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	438	498	314	444
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	72	101
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	15	15	214	373
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	1445	2514
कुल आयातक	मी.ट.	453	513	529	817
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	117	180
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	870	781	704	809
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	81	93
अन्य भारती उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	406	375	374	438
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	92	108
कुल मांग	मी.ट.	1,729	1,650	1,607	2,065
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	93	119
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	50.30	47.33	43.80	39.18
अन्य उत्पादक	%	23.48	22.73	23.28	21.21
संबद्ध देश- चीन जन.गण.	%	25.36	30.20	19.57	21.51
अन्य देश	%	0.86	0.91	13.35	18.07
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध आयात					
कुल आयातक	%	96.69	97.08	59.36	54.34
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	36.20	41.75	29.51	37.34
खपत	%	25.36	30.20	19.57	21.51

उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

(क) संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में यह वृद्धि संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद हुई है।

(ग) कुल मांग की तुलना में अधार वर्ष की अपेक्षा जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

(घ) जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है।

(ङ) आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मांग के अनुरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी भारी गिरावट आई है।

घरेलू उद्योग पर संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव

29. घरेलू उद्योग पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कीमत प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। कीमत कटौती की मात्रा का आकलन करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों के पहुंच कीमत के साथ की है। निवल बिक्री प्राप्ति का आकलन सभी रिबेटों और करों को घटाने के बाद किया गया है। लागू पाटनरोधी उपाय पर विचार करने के बाद भी आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की गई है।

कीमत कटौती

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
कीमत कटौती					
निर्धारित कीमत - चीन जन.गण.	रु. किग्रा.	103.55	100.32	150.82	110.76
सीआईएफ कीमत - चीन जन.गण.	रु. किग्रा.	102.53	99.33	149.32	109.67
आयातों की पहुंच कीमत	रु. किग्रा.	115.73	107.00	160.85	118.14
शुल्क सहित आयातों की पहुंच कीमत	रु. किग्रा.	136.89	125.91	182.11	140.55
निवल बिक्री प्राप्ति	रु. किग्रा.	***	***	***	***
शुल्क रहित कीमत कटौती	रु. किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	% range	20-30	20-30	10-20	20-30
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	रु. किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	% रेंज	1-10	10-20	1-10	1-10

30. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से एम बी टी एस के आयातों की पहुंच कीमत मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के साथ भी घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम है। चीन जू.गण. से आयात के कारण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भारी कटौती हो रही है।

कम कीमत पर बिक्री

31. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ करते हुए निम्नानुसार कम कीमत पर बिक्री की मात्रा का निर्धारण किया है :

विवरण	इकाई	2009-10
कम कीमत पर बिक्री		
क्षति रहित कीमत	रु. किग्रा.	***
आयातों की पहुंच कीमत	रु. किग्रा.	***
कम कीमत पर बिक्री (रु. किग्रा.)	रु. किग्रा.	***

32. उपर्युक्त से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से एम बी टी एस के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है अतः संबद्ध देश से हुए आयातों का घरेलू उद्योग की कीमत पर हासकारी प्रभाव पड़ा है।

कीमत हास/न्यूनीकरण

33. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या संबद्ध देश से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में हास/न्यूनीकरण हो रहा था, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत की तुलना क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत के साथ की है जिसका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	136	103
निवल बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	97.98	128.86	104.07

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान एम बी टी एस की बिक्री लागत और निवल बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। अतः जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए कीमत हास/न्यूनीकरण का पता नहीं चलता है।

ज. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

34. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच में समर्स्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

उत्पादन, बिक्री, क्षमता तथा क्षमता उपयोग

35. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता तथा क्षमता उपयोग निम्नानुसार दर्शाया गया है:

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
क्षमता	मी.ट.	1550	1820	1820	2250
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	117	145
उत्पादन	मी.ट.	1211	1193	1066	1189
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	88	98
क्षमता उपयोग	%	78.13	66	59	53
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	75	68
घरेलू बिक्री	मी.ट.	870	761	704	809
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	81	93
मांग	MT	1,729	1650	1607	2065
मांग की % के रूप में बिक्री	%	50.30	46	44	39
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	87	78

36. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि एम बी टी एस के घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता और उत्पादन में समग्र रूप में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और परिणामी बिक्री में गिरावट आई है जो कि देश में संबद्ध वस्तु की बढ़ती हुई मांग के बावजूद हुई है।

लाभप्रदता

37. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और लाभ/हानि को नीचे दर्शाया गया है :

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
बिक्री की लागत	रु / किंग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	136	103

निवल बिक्री कीमत	रु / किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	97.98	128.86	104.07
लाभ/हानि	रु / किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	32.16	75.10	112.29
घरेलू बिक्री पर पी बी टी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	43	65	96
घरेलू बिक्री पर पी बी आई टी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	44	72	96

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान एम बी टी एस के घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है और घरेलू उद्योग को लाभ हुआ है। प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत में प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए लाभप्रदता की जांच की है। यह पाया गया है कि समूची क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत, दोनों में वृद्धि हुई है। परिणामतः जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है।

रोजगार, उत्पादकता तथा मजदूरी

39. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के बारे में स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
कर्मचारी	सं.	8	8	8	6
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	75
मजदूरी	लाख रुपए	47	56	30	29
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	65	63
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.ट./दिवस	3	3	3	3
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	88	98
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	151	149	133	198
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	88	131

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एम बी टी एस के घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन में सुधार होने के कारण सुधार हुआ है तथा प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग एक बहुउत्पाद कंपनी है और इसलिए घरेलू उद्योग के रोजगार और प्रदत्त मजदूरी वर्तमान मामले में क्षति के मूल्यांकन का उचित मापदंड नहीं हो सकता है।

निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह

41. नकद लाभ और निवेश पर आय के बारे में स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
निवेश पर आय - एन एफ ए आधार पर	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	88	110
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	49	69	96

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश पर आय में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग आधार वर्ष की तुलना में नकद लाभ का स्तर प्राप्त नहीं कर सका।

मालसूची

विवरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
औसत मालसूची	मी.ट.	242	127	92	67
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	38	28

43. आधार वर्ष की तुलना में क्षति अवधि के दौरान एम बी टी एस की मालसूची में भारी गिरावट आई है।

पाटन मार्जिन की मात्रा

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन अत्यधिक और न्यूनतम सीमा से अधिक है। जोच अवधि के दौरान संबद्ध देश से निर्यातों की भारी मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से एम बी टी एस का पाटन जारी रहने की संभावना है।

वृद्धि

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, संबद्ध देश से आयात मात्रा में मामूली वृद्धि हुई है, तथापि, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, लाभप्रदता और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही है जबकि क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, नकद लाभ और बाजार हिस्से के संबंध में यह नकारात्मक रही है।

झ. क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

46. घरेलू उद्योग ने क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति जारी रहने की संभावना के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार तर्क दिए हैं:

1. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के पास संबद्ध वस्तु की व्यापक उत्पादन क्षमताएं हैं। वर्तमान शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से पाटन में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी और अंततः घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
2. संबद्ध देश से घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कीमत कटौती हो रही है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है, तो इस बात की स्पष्ट संभावना है कि कीमत कटौती में आगे और वृद्धि होगी। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में और अत्यधिक कीमत कटौती होने के कारण घरेलू उद्योग उस कीमत से बराबरी करने के लिए बाध्य होगा जिस कीमत पर आयात हो रहे हैं ताकि वह बाजार में बना रहे जिससे कंपनी को घाटा होगा।
3. लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध देश से आयात काफी अधिक मात्रा में हो रहे हैं। पाटनरोधी शुल्क के बिना पहुंच कीमत पर कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा काफी अधिक है जिससे लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना प्रबल होती है।
4. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की बेशी क्षमताओं के बारे में निम्नलिखित तालिका उपलब्ध कराई है। आंकड़ों की पुष्टि संबद्ध देश की संबंधित कंपनियों की वैबसाइट में उपलब्ध सूचना द्वारा की गई है।

एम बी टी एस उत्पादक	क्षमता (एम टी ए में)
रोंगर्चैंग कैमिकल जनरल फैक्ट्री कं. लि.	2400
कार्शिंग कैमिकल कं. लि. शेनयांग	1000
तियानजिन इसट्रीकोन रबड एडीटिप्स क. लि.	12000
नानजिंग यूनियन रबड एंड कैमिकल क. लि.	2400
चाइना सनसाइन कैमिकल होल्डिंग लि.	7000
झोंगज्ञाऊ डबलविंगर कैमिकल प्रोडक्ट क. लि.	3600
हेनान कुईलुन कैमिकल क. लि.	3000
मेयर्स इंक.	1200
झोंगजियांग झेबांग कैमिकल इंट. कं. लि.	2000
हेबाई स्मार्ट कैमिकल्स क. लि.	1200
जिनजियांग हुवर्लई फाइन कैमिकल क. लि.	10000
लिंगवैल रबड कैमिकल (हेबी) क. लि.	1440
हेनान किंगवे कैमिकल्स	3600
डेलियन रिकॉन कैम. क. लि.	2400
विंगडाओ झोंगजियान रबड कैमिकल क. लि.	15600
निंगबो एक्टमिक्स पॉलीमर क. लि.	10000
कुल ज्ञात क्षमताएं	78840
खपत	20766
बेशी क्षमता	58074

(iv) निर्णायक और नई जांच में क्षति की जांच अलग-अलग होती है। विधिक मानक भी अलग-अलग हैं। नई जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक क्षति, वास्तविक क्षति के खतरे अथवा वास्तविक प्रतिगमन का निर्धारण करना अपेक्षित होता है जबकि किसी निर्णायक समीक्षा में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए क्षति जारी रहने या उसकी संभावना होने पर विचार करना अपेक्षित होता है। ये दोनों एक समान नहीं हैं। क्षति की संभावना को क्षति के खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता।

एटीएमए के अनुरोध

47. यह तर्क दिया गया है कि तथ्यों के आधार पर पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने का कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए निर्णायक समीक्षा जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है और निर्धारित प्रपत्र में तथा ढंग से सूची प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि आई बी आई एस लोट से प्राप्त सूचना में लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के अत्यधिक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री संबंधी प्रभाव का पता चलता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन के कारण जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से उत्पादों के आयातों के कारण निरंतर क्षति हो रही है। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने और खासकर उस स्थिति में जब पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद जांच अवधि के दौरान अत्यधिक पाटन मार्जिन है और संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के पास भारी बेशी क्षमताएं उपलब्ध हैं, क्षति जारी रहने की संभावना है।

ii.

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

49. प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु चीन जन.गण. से हुए आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। इस प्रकार तुलना किए जाने पर क्षति मार्जिन निम्नानुसार बनता है:

विवरण	इकाई	चीन जन.गण.
एन आई पी	रु. / किग्रा.	***
पहुंच कीमत	रु. / किग्रा.	***
क्षति मार्जिन	रु. / किग्रा.	***

ट

कारणात्मक संबंध

50. प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध की महत्ता और प्रासंगिकता के बारे में किए गए अनुरोधों की जांच की है। धारा 9 क(5) के अनुसार यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार किए बिना पाटन और क्षति की संभावना और

शुल्क को जारी रखने की जरूरत की जांच करना अपेक्षित है कि क्या समीक्षा जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात हुआ है अथवा नहीं। इस बात की जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली में सूचीबद्ध अन्य मापदंडों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, निम्नानुसार नोट किया जाता है :

अन्य देशों से मात्रा और कीमत

51. जैसा कि आयात आंकड़ों से देखा जाता है जिस अन्य देश से जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का भारी आयात हुआ है, वह बेल्जियम है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि बेल्जियम से आयात कीमत संबद्ध देश की कीमत से अधिक है।

मांग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

52. यह नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध उत्पाद की मांग में कोई कमी नहीं आई है। अतः मांग में संभावित गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हुई है। इन वर्षों के दौरान भारतीय बाजार में उत्पाद की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। खपत की पद्धति में भी किसी परिवर्तन का कोई संकेत नहीं है।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

53. संबद्ध उत्पाद के आयात किसी भी रूप में सीमित नहीं होते हैं और ये देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। घरेलू उत्पादक एक-दूसरे के साथ और साथ ही साथ संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमतें संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। इसके अलावा किसी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह भी पता चल सके कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

प्रौद्योगिकी विकास

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया भी छिटपुट तकनीकी या प्रौद्योगिकी विकास के साथ नितांत स्थिर हैं। याचिकाकर्ता द्वारा लगाई गई और संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

निर्यात निष्पादन

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त क्षति विश्लेषण केवल याचिकाकर्ता के घरेलू प्रचालनों के संबंध में किया गया है और इस प्रयोजनार्थ निर्यात निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

56. उपर्युक्त कारणेतर विश्लेषण से यह पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य ज्ञात कारक की वजह से नहीं हुई है।

व. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

57. पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा

की स्थिति को बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा; और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ड निष्कर्ष

58. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

- (i) पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है।
- (ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- (iii) यह वास्तविक क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहने के कारण क्षति होने की संभावना है।
- (iv) लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद और संबद्ध देश के पास उपलब्ध बेरी क्षमताओं की अत्यधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए जांच अवधि के दौरान भारी पाटन मार्जिन के कारण पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित आयात होने और परिणामी क्षति होने की संभावना है।

ढ. सिफारिशें

59. निर्धारित नियमों के अनुसार पाटन, क्षति और पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई खति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू और पूर्ण करने के बाद तथा संबद्ध देश के बारे में सकारात्मक पाटन मार्जिन एवं संबद्ध देश से आयातों के पाटन और उनकी वजह से हुई क्षति की संभावना का सकारात्मक निर्धारण की पुष्टि करने के बाद और यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति रोकने के लिए संबद्ध देश के बारे में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निम्नलिखित प्रपत्र में और ढंग से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाने की संस्तुति करना आवश्यक समझते हैं।

60. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

संख्या	उत्पादक का नाम	प्रस्तु का विवरण	उत्पादन का दरमा	गियात का दरमा	उत्पादक	नियोजित	शुल्क राशि (अमेरिकी डॉलर)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	381210 381220 381230 293420 292520	कुछेक रबड रसायन (एमबीटीएस) डाइवेनज़ोथियाजोल डाईसल्फाइड	चीन, गण.	चीन, गण.	कोई	कोई	0-23
2.	- वही -	- वही -	चीन, गण.	कोई	कोई	कोई	0-23
3.	- वही -	- वही -	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई	कोई	कोई	कोई	0-23

61. केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इस आदेश के खिलाफ जांच परिणाम के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2011

FINAL FINDINGS

Subject : Final Findings of Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty imposed on imports of Certain Rubber Chemicals namely 'MBTS' originating in or exported from China PR.

F. No. 15/9/2010-DGAD.—Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules).

A. BACKGROUND

Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), definitive anti-dumping duty was originally imposed vide notification No. 87/2005-Customs dated 27th September, 2005, in pursuance of Designated Authority's Final findings No.14/09/2004-DGAD dated 6th July, 2005, on import of Certain Rubber Chemicals (MBTS) (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR, (hereinafter referred to as the subject country/territory).

2. And whereas, in view of the order of the Hon'ble Delhi High court in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd v/s Designated Authority, Writ Petition (Civil) No. 16893 of 2006 and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of AD Rules, the Authority issued a public notice dated 26th July, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the sunset review investigation to review the need for continued imposition of duty in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

B. PROCEDURE

3. The following procedure has been followed in the present investigation:

- i. The Embassy of the subject country in India was informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
- ii. The Authority sent copies of initiation notification dated 26th July, 2010 to the Embassy of the subject country and the domestic industry, known exporters from the subject country, known importers and other interested parties, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file the questionnaires' responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to the Embassy of the subject country along with a list of known exporters / producers with a request to advise the exporters/ producers from the subject country to respond to the questionnaires within the prescribed time.
- iii. Questionnaires were sent to the following known exporters from the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules to elicit relevant information:

S.N.	Company's Name
1.	China Sunine Chemical Holdings Ltd., China PR
2.	Rongcheng Chemical General Factory Co., Ltd., China PR
3.	Shenyang Northeast Auxiliary Chemical Industry Co., Ltd, China PR
4.	Meyors Chemical Inc Limited, China PR
5.	Linkwell Rubber Chemicals Co.,Ltd., China PR
6.	Puyang Willing Chemical Co., Ltd.

None of the Exporters/producers from the subject country filed the questionnaire response.

- iv. Questionnaires were sent to the following known importers, users and the associations of the subject goods in India for providing necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

S.N.	Company's Name
1.	J.K. Industries Ltd. Kolkata
2.	CEAT Limited, Mumbai
3.	Apollo Tyres Ltd., Kochi
4.	Birla Tyre, Kolkata
5.	MRF Limited, Chennai
6.	Metro Tyres Ltd., Ludhiana
7.	Poddar Tyres Ltd., Ludhiana
8.	Raison Ind. Ltd., New Delhi
9.	Rubber Products Ltd., Thane

S.N.	Association's Name
1.	Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA)

v. Importers questionnaire response has been submitted by CEAT Limited and Apollo Tyres Limited.

vi. The imports data for the period of investigation and preceding three years was called from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), which was received by the Authority.

vii. In response to the notification issued by the Authority dated 26th July 2010, the Authority received an application from M/s National Organic Chemicals Industries Ltd (NOCIL) requesting for the review, continuance and enhancement of anti-dumping duty in force against the dumping of Rubber Chemical (MBTS) in the Indian market by the producers and/or exporters from the subject country. Besides, M/s Automotive Tyres Manufacturers Association (ATMA) filed their submissions in this regard. However, none of the producers/exporters from the subject country has responded to the initiation notification.

viii. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

ix. As stated, the application for continuation of the anti-dumping duty was received from M/s NOCIL, which is a major producer of the subject goods in India. It has submitted the information/data for undertaking the injury analysis. The Authority has examined the information furnished by the company to the extent possible on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) to analyze the injury suffered and to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if the anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

x. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in public hearing held on 2nd May 2011. The parties who presented their views in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered, to the extent relevant, in these findings.

xi. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2009–31st March 2010 (POI). However, injury analysis covers the periods April 2006–March 2007, April 2007–March 2008, April 2008–March 2009 and the POI.

xii. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry.

xiii. In accordance with the Rule 16 of the AD Rules, the essential facts under consideration before the Authority in the instant investigation were disclosed to the concerned interested parties. The comments received on the disclosure statement, to the extent considered relevant, have been duly examined in the Authority's findings.

xiv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided the necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority recorded the findings on the basis of the information and facts available.

xvi. *** In these findings represents the information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions made by NOCIL

4. The domestic industry made the following submissions:
 - (i) The product under investigation in the original investigation and present review is Rubber Chemical (MBTS). MBTS is extensively used in the manufacture of various rubber products. It is an accelerator and is also used in manufacturing of automotive tyres, conveyor belts and footwear industry.
 - (ii) The Authority in the original investigation noted that there is no dedicated ITC HS Classification for the subject goods and product under consideration is classified under various subheadings of customs classification heads 38.12.10, 38.12.20 and 38.12.30 as well as under 29.34.20 and 29.25.20 (at six digit levels) of the Customs Tariff Act and ITC HS classification. However, the Authority also noted that the product is known by its respective trade name and the chemical description as indicated above.
 - (iii) The goods produced by the domestic industry are like article to the imported product. There is no known difference in the product under consideration produced by the Indian industry and subject goods exported from the subject country. The issue of product under consideration and like article was examined in detail by the Designated Authority in the original investigation and it has been held that the imported and domestic products are like article.
 - (iv) Present review investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation.

Submissions made by other interested parties

5. None of the other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration, like articles and scope of the present investigation.

Examination by the Authority

6. The Authority notes that since the present investigation is a Sunset review investigation, the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation. The Authority in its final finding vide Notification No. 14/09/2004-DGAD dated 6th July, 2005, inter-alia, held that the product under consideration is certain specific rubber chemical, namely, MBTS, used in manufacture of rubber products. The chemical name of MBTS is Dibenzothiazole disulphide and its other trade name is Accelerator DM. MBTS is manufactured by oxidation of sodium salt of MBT using suitable oxidizing agents. It is mainly used in automotive tyre and tubes industry and also in conveyor belting and footwear industry amongst others.

D. Scope of the Domestic Industry**Submissions made by the domestic industry**

7. The present investigation has been undertaken *suo motu* by the Authority. NOCIL is a major producer of the subject goods in the Country. As regards the production of the subject good by other producers, no published information is available. The applicant satisfies the requirement of standing within the meaning of the AD Rules.

Submissions made by other interested parties

8. None of the interested parties has made any submission in respect of the standing of the "domestic industry".

Examination by the authority

9. Rule 2(b) under the AD Rules provides as follows:-

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves the importers thereof in such case the term 'Domestic Industry' may be construed as referring to the rest of the producers only.

10. In the present review investigation, M/s NOCIL Ltd. has responded to the initiation notification. As per the information on record, M/s NOCIL Ltd. is a major producer of the subject goods in India. Therefore, M/s NOCIL Ltd satisfies the requirement of 'domestic industry' within the meaning of the AD Rules for the subject goods.

E. Dumping Determination

Normal Value

Submissions made by the Domestic Industry

11. The domestic industry has contended as follows:

- (i) The preferred methodology for the determination of Normal Value is the selling price of the exporter concerned for sale in the domestic market. However, such information is available with the exporters concerned only. There is no public information available in this regard. It is not the argument of any interested party that such selling price of the foreign producers in their domestic market was readily available and the petitioner chose to ignore the same. It is also relevant to point out that the petitioner can be expected to provide such information as is reasonably available to the petitioner. In fact, in a large number of cases, the Designated Authority has considered the prices published in trade journals. Such prices need not be the prices of the domestic producers. Such prices generally are the prices at which the product has been purchased for consumption in the exporting country.
- (ii) It would thus be seen that the Rules emphasis on 'the price when meant for consumption' and the same must be distinguished with 'the price at which goods has been sold'. "In the original investigations, the Designated Authority has not granted market economy treatment to the responding exporter from China PR and determined the normal value of the subject goods in the China PR on the basis of the constructed normal value based on the 'price paid or payable in India' duly adjusted for the reasonable profit margin". Since the present application is for the review of the existing measures, petitioner requests the Authority to consider the same methodology to calculate the normal value for the purposes of the non-market economy.
- (iii) The petitioner has adopted its export price to Europe to determine the price at which Rubber Chemicals are being sold for consumption in European market.
- (iv) Petitioner submits that the Rubber Chemicals constitutes specialty chemicals and have extremely limited market globally. These are neither widely traded commodity, nor are the prices of these products published/tracked by trade journals. In fact, globally there are very few producers (probably below 10), who sell the product directly to the customers (at least tyre segments). Therefore, the price at which the European producers have sold the product in the domestic market is not at all publicly available.
- (v) In view of the above, and considering that the actual information is in possession of the foreign producers, the Authority should consider the evidence of the price at which goods have been sold for consumption in the domestic market of Europe for

the determination of normal value. Such a methodology is not only legally permissible, but is also appropriate.

- (vi) It was suggested by ATMA that the prices from Trade Journal could have been adopted. The petitioner submitted that there is no Trade Journal which reports prices of these products. If such prices were indeed available; nothing prevents ATMA from providing this information to the Designated Authority. Anti-dumping investigations cannot be seen as an investigation where only the domestic industry would provide information and evidence and all other parties' role would be restricted to mere rejoinder. Nothing preventing ATMA from providing relevant information, if ATMA considers that such information is readily available.
- (vii) The Authority in the original investigation provided a detailed reasoning for discarding the market economy treatment to the exporters/producers from China PR. Since, none of the exporters/ producers has filed any questionnaire response to rebut the claim of non-market economy, the status as accorded in the original investigation should be considered for the exporters / producers from the subject country.

Submissions made by other interested parties

- 12. The Automotive Tyre Manufacturer's Association on behalf of importers and users have, *inter alia*, contended as follows:
 - (i) The procedure adopted for the Normal Value and export price determination for the subject country is WTO incompatible and not in accordance with the Indian Rules.
 - (ii) The interpretation of Section 9A of the Act is highly misleading. It is Para 7 of Annexure I, which needs to be applied for the determination of normal value for a non-market economy country. In the matter of *Shenyang Mastsushita S. Battery Co. Ltd v. Exide Industries Ltd. & Others*, the CESTAT has provided a hierarchy in Para 7 for the determination of Normal Value for a NME country. The same needs to be followed in the present matter.
 - (iii) The normal value in case of the non-market economy shall be determined on the basis of the price or cost of production in an appropriate third country and only if this is not possible, then the Authority can resort to any other reasonable methodology.
 - (iv) In the original Investigation as well, the normal value was based on "any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted if necessary." The same methodology should be adopted in the present case as well.

- (v) NOCIL's export price to EU is not a reasonable basis in as much as the same bears no connection with the costs and prices in China PR.
- (vi) There is inconsistency in the deductions made while calculating the export price for the subject country as claimed by the domestic industry in the petition and the annexure attached thereto. Authority is requested to analyze the same in detail.
- (vii) The domestic industry has not provided any basis for the deductions claimed in the calculation of the export price.

Examination by the Authority

13. As regards Normal Value, the Authority has examined the matter as under:

- (i) The Authority notes that this investigation was initiated on *suo motu* basis.
- (ii) However, as regards the ATMA's contention that refers to the submissions of the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry is required to provide information, *inter alia*, on prices at which the product in question is sold when destined for consumption in the domestic markets of the country or countries of origin or export (or, where appropriate, information on the prices at which the product is sold from the country or countries of origin or export to a third country or countries, or on the constructed value of the product) and information on export prices or, where appropriate, on the prices at which the product is first resold to an independent buyer in the territory of the importing Member.
- (iii) Besides, the other interested parties are expected to file their questionnaire responses and thereby assist the Authority to reach an impartial and objective finding. The Authority addressed all known interested parties to make available the relevant information. Since none of the producer/exporter from China PR has co-operated in this investigation and provided any information for rebutting the non-market economy treatment as per para 8(2) of Annexure 1 of the AD Rules, the presumption of non-market economy as per para 8(2) of Annexure 1 of the AD Rules remains un-rebutted. The Authority, therefore, determines the Normal value in accordance with para 7 Annexure I of the AD Rules. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods as are enshrined in para 7 of Annexure I of the AD Rules, the Authority has determined the Normal value by adopting the method of "any other reasonable basis".

14. The Authority, in the absence of sufficient information on record regarding other alternative methods as provided in para 7 of Annexure 1 to the AD Rules, has constructed the Normal value for all producers/exporters of China PR considering the international prices of major raw materials, optimum consumption norms and conversion cost as available on record and a reasonable profit. The Normal value so determined works out as US\$ ***/Kg.

Export Price

15. In relation to export price, the Authority has examined the matter as under:

- i. The Authority notes that no exporter/producer from the subject country has responded to the initiation notification nor provided information in the form and manner prescribed for the purpose. In view of the non-cooperation by the exporters/producers, the Authority proceeds to determine the 'Export price' on the basis of information available on record.
- ii. In this regard, the Authority examined as to whether the import statistics provided by IBIS and DGCI&S could be used to determine the Export price of the subject goods from the subject country during the relevant period. It is seen that the domestic industry has claimed volume, value and import price on the basis of information provided by IBIS. The Authority has adopted the import data from IBIS source, which has reported a higher volume of imports than DGCI&S, in order to determine volume and value of imports for the purpose of present investigation.
- iii. Thus, the Authority has determined the weighted average import price for the product under consideration on the basis of information provided by IBIS. It is seen that the import prices as reported in the IBIS are on CIF basis. In view of the non-cooperation by the exporters/producers from the subject country, the Authority has determined the 'Export Price' on the basis of information available on record.
- iv. Accordingly export price has been calculated on weighted average CIF basis. To arrive at the net export price, expenses on inland freight, ocean freight and insurance, port charges and commission have been deducted. By this method, the net export price has been determined as under:

Particulars	Unit	China PR
Import volume	MT	444
Import value	Rs. Lacs	491.89
CIF import price	Rs./Kg	109.67
Exchange rate	Rs./US\$	48.30
CIF export price	US\$/Kg	2.27
Price adjustments (total)	US\$/Kg	***
Ex-factory export price	US\$/Kg	***

Dumping Margin

16. On the basis of comparison of the Normal value and Export price (both at Ex-factory

level) so determined, the dumping margin during the POI for all exporters/producers from the subject country has been worked out as follows:

	Unit	Amount
Constructed Normal Value	US\$/Kg	***
Net Export price	US\$/Kg	***
Dumping Margin	US\$/Kg	***
Dumping Margin	% range	10-20

F. Continuation or recurrence of dumping:

17. The domestic industry has, *inter alia*, contended as follows:

- i. In the present case, the exports from the subject country continued to be made at dumped prices, establishing that the exporters would continue to export the subject goods at dumped prices in case of cessation or revocation of anti-dumping duty.
- ii. Dumping margin determined in the present investigation is above *de minimis* as well as significant. This is the situation when the anti-dumping duty was in existence.
- iii. In the previously concluded investigation also, the Authority had found significant dumping margin and concluded the investigation with the imposition of the antidumping duty on the imports of the subject good from the subject country. Inspite of the Anti-dumping duty in existence, the dumping from the subject country has continued to be significant.
- iv. The exports of the subject goods by the exporter/producer from the subject country to third countries are also at dumped prices.
- v. The prices prevailing in the Indian market are quite attractive for the foreign producers to export the significant volumes, in case the anti-dumping duty is revoked. The price-undercutting is significantly positive even at the current level of anti-dumping duty. The petitioner has calculated price undercutting without anti-dumping duty which comes out to be significantly positive clearly showing that should the present anti-dumping duty is revoked or allowed to cease, the price attractiveness of Indian market would further increase for the foreign producers which would result in further increase in imports at dumped prices.
- vi. Considering the demand with the capacity in China PR, it is obvious that there is huge surplus capacity in China PR over demand. In the event of revocation of anti-dumping duty, these exporters are likely to divert huge volume of dumped exports to large and growing market in India thereby leading to continuation of dumping. The evidences as to the excess capacities have been provided along with the submissions filed.
- vii. Domestic industry will suffer significant financial losses, if the duty is revoked or allowed to cease and the domestic industry is forced to match the prices.

vii. The foreign producers have preferred non-cooperation and therefore the Authority should apply best available information.

Submissions made by ATMA

18. ATMA has contended that there is no case for recurrence of dumping and injury and hence the SSR investigation should be terminated. It has further contended that:

- i. The claim of confidentiality by domestic industry is unwarranted.
- ii. The use of word "likely" as provided under Article 11.3 of the AD Agreement suggests that an affirmative likelihood determination may be made only if the evidence demonstrates that the dumping would be probable if the duty were terminated and not simply if the evidence suggests that such a result might be possible or plausible. In the matter of *Vinati Organics Ltd v. Designated Authority*, it has been held by the CESTAT that the point required to be taken into consideration by the Authority should be based on some positive evidence and not on mere surmises and conjectures.
- iii. Even in sunset review investigation, the designated authority is required to analyse the domestic industry performance based on the parameters laid down in Annexure II. If the domestic industry's performance has improved on account of various injury parameters, the Authority may withdraw the duty.
- iv. The domestic industry has made unsubstantiated claims for likelihood of continuation or recurrence of dumping in the petition.
- v. In the light of improved performance of the domestic industry, the argument of likelihood of dumping is unwarranted.
- vi. Recurrence of dumping and injury has to be based upon imports coming into India and it cannot be based upon the exports to third countries. Authority cannot base the normal value in subject country upon the export price of subject goods by NOCIL to EU.
- vii. Baseless claims are made by the domestic industry with respect to the excess capacities in the subject country. The claim of surplus capacities is unsubstantiated. Mere surplus capacity does not provide for threat of material injury. Indian Spinner Association v. Designated Authority clearly held that the existence of surplus production capacity cannot be taken as posing a clearly foreseen and imminent threat of injury.

Examination by the Authority

19. The Authority notes that the information provided by both parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing the information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

20. The Authority notes that none of the exporters/producers of MBTS from China PR has responded to the initiation notification and provided information in the form and manner

prescribed. However, the Authority notes that the information made available by IBIS shows the imports of MBTS as 444 MT from China PR during POI. It is further noted that there is a positive dumping margin in respect of imports of the subject good from China PR despite the anti-dumping duty in force. Thus the Authority is of the view that there is likelihood of continuance of dumping of MBTS from China PR if the anti-dumping duty is allowed to be withdrawn, given the fact that the subject country has a high level of surplus capacities for production of the subject goods, as per evidence which is dealt later in this disclosure statement.

G. Injury

Views of Domestic Industry

21. The submissions made by the domestic industry with regard to injury and causal link, in brief, are as follows:

- i. Imports of the product under consideration have continued. In fact, the volumes have increased in absolute terms over the years. The imports volume has remained quite significant, despite the existing anti dumping duty. Further, the volume of imports is far higher than the volume of imports established during the previous investigations. The volumes are higher than the volumes prior to the imposition of anti-dumping duty. This clearly establishes likelihood.
- ii. The market share of the dumped imports continued to increase and that of the domestic industry declined. Since imports are cheaper even after adding the anti-dumping duty, the consumers have resorted to imports. There is no other reason for these imports.
- iii. The claim of the importers that the imports from Belgium have increased, it is submitted that the import price from Belgium are much higher when compared with the import prices from China PR.
- iv. The import price represents the prices at which goods have been imported in India, but does not represent the price at which consumers are getting the product. Since these goods are being imported by rubber chemical manufactures, the resale price is significantly higher than the price at which goods have been imported. The competition to the domestic industry in these imports is from the resale price of the imported product. Such resale price being significantly higher, imports from third countries are not a principal cause of injury to the domestic industry.
- v. Landed price of imports are below the non-injurious price of the product under consideration. The landed price declined steeply in 2007-08, even when the cost had increased. Resultantly, the domestic industry was forced to reduce the prices even when the costs were rising. Despite this reduction in the prices by the domestic industry, the import volumes increased.
- vi. In 2008-09, the market was hit by recession. In 2009-10, as the markets recovered from recession and the costs of inputs declined, the cost of production of the domestic industry

declined. The domestic industry also reduced its prices. However, the import prices declined too significantly. Thus, even when the domestic industry reduced its prices, the decline in the import prices was more than the decline in the selling prices. Resultantly, the volume of imports increased significantly.

vii. Petitioner has provided sufficient evidence to prove that the confidentiality claims are warranted both in the light of facts and law. In all the ongoing investigations wherein the rubber chemicals are considered, petitioner has not disclosed any of information claimed confidential. Such is the practice of the industry wherein no player discloses any information in the market and treat it as business sensitive information as the industry is a closed business industry. Disclosure of such information would jeopardise its market as customer will then take advantage of the means and force the company to reduce its prices.

viii. Imports of the product under consideration are undercutting the prices of the domestic industry in the market.

ix. The capacity of the producers and exporters to maintain a significant market share inspite of anti-dumping duty in existence clearly suggests that revocation of the present duty would lead to consumers increasingly shifting to the subject country.

x. The significant positive undercutting, follows that the market share of the subject country would increase on cessation of anti-dumping duty. The price undercutting without anti-dumping duty is significantly high. The domestic industry will be forced to reduce the prices to significant extent in the event of cessation of anti-dumping duty.

xi. Chinese producers have intensified dumping by absorbing the applicable duty. The consumers have been able to import these products without the payment of anti-dumping duty in view of the exemption from the payment of anti-dumping duty exemption schemes.

xii. The production of the domestic industry declined in the period of investigation inspite of increase in demand. The domestic industry enhanced its capacities in view of current and potential demand; the domestic industry was unable to fully utilize its capacity.

xiii. The profits of the domestic industry improved with the imposition of duty, which declined again with the decline in sale volume. The profit before interest & depreciation also declined in the current injury period.

xiv. Even when the performance of the domestic industry has not deteriorated, the same is due to imposition of anti-dumping duty. The performance of the domestic industry could improve further, but for dumped imports in the market. Further, performance has remained sub-optimal in view of continued presence of dumped imports.

xv. With regard to the argument of the association regarding the extension of the investigation period, it is submitted that the Petitioner has not sought the extension of the investigation period. The petitioner has simply considered the performance of the domestic industry in the current injury period with the previous years, as the Designated Authority is required to assess both actual performance and likelihood at the time of the sunset review. The

performance for the four years period is relevant for assessment of injury to the domestic industry, whereas the assessment of injury for the longer period is necessary to determine likelihood of injury.

xvi. The present investigations are sunset review investigations. In the event of the Designated Authority holding that the domestic industry has not suffered continued injury, the Designated Authority may kindly examine the likelihood of injury.

Submissions made by other interested parties

22. Following submissions have been made by ATMA on behalf of consumers and users of the subject goods. There is no response from any other interested party in the instant matter:

- (i) Domestic Industry's claim to extend the injury period is not permitted as the extended period is against the law and regular practice of Designated Authority. In several past cases only four years have been considered. When initiation notification deals only with four years, no further examination can be carried out in this regard.
- (ii) The imports from other countries are much higher than the imports from subject country. Therefore, any decrease in the production, sales or market share of the domestic industry cannot be attributed to the import from the subject country. The imports from other countries especially Belgium have gained market share to the considerable level.
- (iii) There has been an increase in Capacity utilization, Capacity and Production of the Domestic Industry for the subject product.
- (iv) The profitability of the domestic industry has increased. It has even made fresh investments. It is therefore imperative that the profits of the domestic industry would be low as part of the profits has been diverted to recover the running cost of the new investments.
- (v) The employment and salary figures also support other data on profits which has shown steady and healthy increases during the period of levy of anti-dumping duty.
- (vi) Domestic industry has admitted itself that the inventory level has declined. Also, a low level of inventory does not support the case of the domestic industry for the continuation of duty.
- (vii) Further, ROCE has also increased considerably. The domestic industry has been able to achieve better returns on investment during the POI.

- (viii) There is no price undercutting to the domestic industry as the CIF value of the imports have either increased or remained constant during the period of levy of anti-dumping duty.
- (ix) There is no price suppression and depression to the domestic industry as the domestic industry is able to increase its selling price and also the landed price and CIF value of imports have increased during the period of investigation.
- (x) In the view of the improvement in the performance of the domestic industry in various parameters, Authority should reject the claims of the domestic industry with respect to the injury.
- (xi) The demand for the subject product declined over the injury period except for the period of investigation. Stagnated demand is the result of injury to the domestic industry.
- (xii) There has been significant decline in the export sales for the subject product of the domestic industry.
- (xiii) There exists no causal link between the injury to the domestic industry and imports of the subject goods from the subject country.
- (xiv) The change of base year by DI is misleading:- Notification no. 15/14/2009-DGAD issued by the DGAD for initiating Sunset Review very clearly provides that injury analysis would cover the years 2006-07, 2007-08, 2008-09 and 2009-10 and wherein year 2006-07 has been considered as a base year. However the DI in their submissions has argued that a longer injury period should be taken into consideration by the Hon'ble DA for assessing injury to the Domestic Industry. In view of the fact that Hon'ble DA as a practice has never allowed a longer injury period than provided for in the notification and the same was also not opposed by the DI at the time of initiation, the argument of DI should be rejected.

Post Disclosure submissions of interested parties:

23. The following submissions are made by the interested parties post-disclosure:

- i) Domestic industry's performance has been significantly positive during POI and the imports from China PR has not led to any volume or price effect on the domestic industry.
- ii) Decline in market share of DI is a result of the increase in the market share of imports from other countries and increase in sales of other domestic producers. This along with market share of imports from China PR severs the causal link between imports from China PR and decline in imports of DI.

- iii) Volume effect on the domestic industry is not due to import of subject goods from China PR, but due to increase in imports from third countries.
- iv) Although there is price undercutting and price underselling effects of subject imports, there is no price suppression/depression effect on the domestic industry during POI as observed by Authority itself.
- v) Both profits as well as NSR of the domestic industry have increased in the POI. This proves that alleged price undercutting and underselling had no effect on the ability of DI to increase its NSR and increase its domestic profits.
- vi) There is significant increase in imports from Belgium and the landed price from Belgium is undercutting the prices of DI.
- vii) In view of significant undercutting by imports from Belgium, Authority should make analysis of injury suffered by DI due to imports from Belgium and the same should not be attributed to imports from China PR.
- viii) DGAD has observed that there has been a decline in cash flow of the DI. However, the same can be due to the investments made for increasing the installed capacity. DGAD should ascertain the correct picture.
- ix) Excess capacity figures provided by DI are irrelevant as the same doesn't have any bearing on the state of domestic industry. There is no certainty that these products will be exported to India.
- x) As regards non-injurious price it is stated that a reasonable return of 22% (pre-tax) on capital employed was allowed by the Authority. Such an assumption that the DI should have a fixed return on capital every year is erroneous.
- xi) The data considered for constructed Normal Value has not been provided.
- xii) Domestic Industry has stated that it would have been appropriate to adopt domestic industry's export price to Europe to determine the normal value i.e. price at which Rubber Chemicals are being sold for consumption in European market as was done in case of PX-13.
- xiii) As regards likelihood of dumping and injury, domestic industry has submitted that imports from subject country continued to enter the Indian market at dumped prices, which establishes that the exporters would continue dumping of subject goods in case of revocation of AD duty.
- xiv) Further, given the significant dumping margin during POI established by the Authority and huge surplus capacities in China over demand, there is likely diversion of large volumes of dumped exports into India.
- xv) If the current Anti-dumping duty is withdrawn and DI is forced to sell at prices matching the landed prices of imports then significant financial losses will be incurred by the DA.
- xvi) The Domestic industry has substantiated the likelihood of dumping and injury by providing sufficient evidence in the written submissions and rejoinders.
- xvii) Improvements in certain injury parameters of DI are bound to result in the advent of applicable anti-dumping duty. However, subject imports are undercutting the prices of DI and landed price of subject imports is below the non-injurious price of the domestic industry.

28/06/2011-7

- xviii) Imports from Belgium are high priced and these imports are being made by producers of other Rubber chemicals in India who are reselling the same in the market. The resale prices of these producers are much higher than the import prices. The level of trade being different The CIF or landed price is not directly comparable.
- xix) The non-injurious price determined for DI is grossly low and may be reviewed.
- xx) Domestic industry has submitted sufficient evidence to prove absorption of applicable anti-dumping duty by the exporters from subject country. If anti-dumping duty is allowed to cease, the exporters would resort to intensified dumping.
- xi) Further there are significant excess capacities with exporters which will be diverted to Indian market in the event of cessation of present anti-dumping duty.

Examination by the Authority

24. The Authority has examined the issue relating to injury as under:

- (i) The Authority notes that AD Rules do not require that the domestic industry must meet the demand of the user industry for getting redressal to its injury on account of dumping.
- (ii) The Authority notes that it has consistently adopted the practice to examine and evaluate the injury data over the injury period. However, in an SSR investigation, the Authority assesses whether the cessation of the duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequential injury.
- (iii) The Authority has found that the dumped imports from subject country have significant price undercutting and price underselling effects on the domestic industry. The Domestic industry has also suffered injury on certain parameters, though it has registered positive performance on certain other parameters like profitability and net selling price.
- (iv) The above scenario obtains when anti-dumping duty on subject imports is in place. Therefore, the Authority has considered a scenario about the state of domestic industry in case of revocation of anti-dumping duty. The likelihood analysis in respect of dumping and injury has been carried out by the Authority for the purpose as mandated under law in case of Sun-Set Review.
- (v) The Authority notes that in case of Sun-Set Review the appropriate parameter to be adopted by the Authority, as laid down in law, is whether the cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Therefore, the Authority, in the present case, has considered the aspect of likelihood of dumping and injury.

- (vi) In this regard, the Authority has found that dumped imports of subject goods from the subject country continued during POI despite anti-dumping duty in place. Therefore, the same is likely to be intensified in case of cessation of duty along with consequential injury to domestic industry. Further, the Authority notes the significant price undercutting and price underselling effects of subject imports inspite of the anti-dumping duty. Furthermore, it is noted that there are large surplus capacities with the producers/exporters of the subject country so far as the subject goods are concerned, which are likely to be find a way in to India in the event of cessation of anti-dumping duty.
- (vii) On the basis of aforesaid analysis, the Authority is of the view that cessation of anti-dumping duty on the subject goods is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to domestic industry.
- (viii) As regards issues raised on non-injurious price for the domestic industry, the Authority notes that the same has been determined in accordance with the principles laid down in Annexure-III to the Anti-Dumping Rules.
- (ix) The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and the submissions made by the interested parties.
- (x) As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the Anti Dumping Rules states as follows.

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments"

- (xi) Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
- (xii) For the purpose of current injury analysis the Authority has examined the volume and prices effects of imports of the subject goods from subject country on the

domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between dumping and injury, if any.

Volume effect

Assessment of Demand

25. For the purpose of the assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producer have been added to the total imports into India, which has been summarized as under:

Particular	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Imports from Subject country	MT	438	498	314	444
Trend	Indexed	100	114	72	101
Imports from Other countries	MT	15	15	214	373
Trend	Indexed	100	101	1445	2514
Total Imports	MT	453	513	529	817
Trend	Indexed	100	113	117	180
Sales of Domestic Industry	MT	870	761	704	809
Trend	Indexed	100	88	81	93
Sale of other Indian Producers	MT	406	375	374	438
Trend	Indexed	100	92	92	108
Total Demand	MT	1,729	1,650	1,607	2,065
Trend	Indexed	100	95	93	119

26. The Authority notes that the demand for subject goods has shown a positive trend and increased significantly in the period of investigation as compared to the base year. The growth in demand during period of investigation over base year was about 19%.

Import volumes and market share

27. Annexure-II (ii) of the AD Rules provides that "while examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports either in absolute term or relative to production or consumption in India". Thus, with regard to the volume of the dumped imports, it has been examined whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

28. The table below indicates the position with regard to import volumes and market share -

Particular	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Imports from Subject country	MT	438	498	314	444
Trend	Indexed	100	114	72	101
Imports from Other countries	MT	15	15	214	373
Trend	Indexed	100	101	1445	2514

Total Imports	MT	453	513	529	817
Trend	Indexed	100	113	117	180
Sale of domestic industry	MT	870	781	704	809
Trend	Indexed	100	88	81	93
Sale of other Indian Producers	MT	406	375	374	438
Trend	Indexed	100	92	92	108
Total Demand	MT	1,729	1,650	1,607	2,065
Trend	Indexed	100	95	93	119
Market Share in Demand					
Domestic Industry	%	50.30	47.33	43.80	39.18
Other Producers	%	23.48	22.73	23.28	21.21
Subject Country-China PR	%	25.36	30.20	19.57	21.51
Other Countries	%	0.86	0.91	13.35	18.07
Subject Imports in relation to					
Total Imports	%	96.69	97.08	59.36	54.34
Production of domestic industry	%	36.20	41.75	29.51	37.34
Consumption	%	25.36	30.20	19.57	21.51

From the above, the Authority notes that:

- a) The volume of imports from the subject country has marginally increased in the period of investigation as compared to base year.
- b) The increase in volume of imports from the subject country has taken place in spite of anti-dumping duty in place on the subject goods.
- c) The market share of subject imports have declined during the POI in comparison with base year in relation to total demand..
- d) The market share of imports from other countries has increased significantly during POI.
- e) The market share of domestic industry in relation to demand has also declined significantly during POI as compared to base year.

Price effect of the subject imports on the Domestic Industry

29. In order to ascertain the price effect of the imports of the subject goods from subject country on the domestic industry, the Authority has examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In order to assess the extent of price undercutting, the Authority has compared net sales realization of the domestic industry with the landed price of imports. The net sales realization was arrived, after deducting all rebates and taxes. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry, even after considering the anti-dumping measure in force.

Price Undercutting

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Price Undercutting					
Ass. Price - China PR	Rs. Kg	103.55	100.32	150.82	110.76
CIF Price - China PR	Rs. Kg	102.53	99.33	149.32	109.67
Landed Price of Imports	Rs. Kg	115.73	107.00	160.85	118.14
Landed Price of Imports with duty	Rs. Kg	136.89	125.91	182.11	140.55
Net Sales Realization	Rs. Kg	***	***	***	***
Undercutting without duty	Rs. Kg	***	***	***	***
Undercutting (%)	% range	20-30	20-30	10-20	20-30
Undercutting with ADD	Rs. Kg	***	***	***	***
Undercutting (%)	% range	1-10	10-20	1-10	1-10

30. From the above, the Authority notes that the landed price of imports of MBTS from the subject country is below the net selling price of the domestic industry even with the existing anti dumping duty. Thus, the imports from China PR are significantly undercutting the selling prices of domestic industry even after levy of existing anti dumping duty.

Price underselling

31. The Authority has assessed the extent of price underselling by comparing non-injurious price of the domestic industry with the landed price of imports, as shown below:

Particulars	Unit	2009-10
Price Underselling		
Non-Injurious Price	Rs. Kg	***
Landed Price of Imports	Rs. Kg	***
Underselling (Rs. Kg)	Rs. Kg	***

32. From the above, the Authority notes that the landed price of imports of MBTS from the subject country is below the non-injurious price (NIP) of the domestic industry. Thus, the imports from the subject country have a price underselling effect on the domestic industry.

Price suppression/depression

33. In order to assess whether the imports from the subject country were suppressing/ depressing the prices of the domestic industry, the Authority has compared the cost of production and net selling price of the domestic industry along with the landed price of imports over the injury period, which is given in the following table:

Particular	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	136	103
Net Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	129	104

The Authority notes that both the cost of sales and net selling price of MBTS increased during POI as compared to base year. Thus, price suppression/ depression does not appear to have taken place for the domestic industry during the POI.

H. Economic Parameters relating to the Domestic Industry

34. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of the subject goods. With regard to the determination of consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

Production, sales, capacity and capacity utilization

35. Production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry moved as shown below:

Particular	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Capacity	MT	1550	1820	1820	2250
Trend	Indexed	100	117	117	145
Production	MT	1211	1193	1066	1189
Trend	Indexed	100	99	88	98
Capacity Utilization	%	78.13	66	59	53
Trend	Indexed	100	84	75	68
Domestic Sales	MT	870	761	704	809
Trend	Indexed	100	88	81	93
Demand	MT	1,729	1650	1607	2065
Sales in % of	%	50.30	46	44	39

demand					
Trend	Indexed	100	92	87	78

36. It is noted from above that the installed capacity and production of the domestic industry of MBTS have gone up in absolute terms. However, there is a decline in the capacity utilization and consequently sales of the domestic industry, which is despite the increasing demand for the subject good in the country.

Profitability

37. Cost of production, net sales realization & profit/loss of the domestic industry is shown below.

Particular	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	136	103
Net Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	97.98	128.86	104.07
Profit/Loss	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	32.16	75.10	112.29
PBT on domestic sales	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	43	65	96
PBIT on domestic sales	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	44	72	96

38. The Authority notes that performance of the domestic industry for MBTS has improved over the injury period and the domestic industry is in profits. The Authority examined profitability by considering the trends in the cost of sales and selling prices over the injury period. It is found that both the cost of sales and the selling prices increased throughout the injury period. Consequently, profitability of the domestic industry improved during the POI.

Employment, Productivity and Wages

39. Position with regard to employment, wages and productivity as follows:

Particular	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Employees	No.	8	8	8	6
Trend	Indexed	100	100	100	75
Wages	Rs.Lacs	47	56	30	29
Trend	Indexed	100	120	65	63
Productivity per day	MT/day	3	3	3	3

Trend	Indexed	100	99	88	98
Productivity per employee	MT	151	149	133	198
Trend	Indexed	100	99	88	131

40. The Authority notes that the productivity of the domestic industry for MBTS improved with the improvement in production. The Authority, however, notes that the domestic industry is a multi-product company and hence the employment by the domestic industry and wages paid may not be an appropriate parameter to evaluate the injury in the instant matter.

Return on investments and cash flow

41. Position with regards to cash profits and return on investments are as follows:

Particular	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ROI - NFA basis	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	60	88	110
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	49	69	96

42. The Authority notes that return on investment made by the domestic industry for MBTS improved over the injury period. The domestic industry could not achieve the level of cash profit in comparison with the base year.

Inventories

Particular	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Average Inventory	MT	242	127	92	67
Trend	Indexed	100	52	38	28

43. The inventories of MBTS have declined significantly over the injury period as compared to the base year.

Magnitude of Margin of Dumping

44. The Authority notes that the dumping margin from the subject country is significant and above *de-minimis* level. In view of large volume of exports from the subject country during the period of investigation, the Authority notes that there is a likelihood of continuation of dumping of MBTS from the subject country, if the applicable anti-dumping duty is allowed to cease.

Growth

45. The Authority notes that while there has been a marginal growth in the import volume from the subject country, the growth of domestic industry in terms of production, profitability and return on investment has been positive over the injury period whereas

with respect to capacity utilization, domestic sales, cash profits and market share has been negative.

Likelihood of continuation or recurrence of injury

46. The domestic industry, *inter alia*, has contended as follows on Likelihood of continuation or recurrence of injury:

1. Producers/exporters in the subject country are having large production capacities of the subject goods. In case of cessation of the present duty, dumping from the subject country would definitely increase and ultimately cause injury to the Domestic Industry.
2. The subject country is causing severe price undercutting to the prices of the Domestic Industry. Should the present anti dumping duty is revoked, there is a clear likelihood that price undercutting would deepen further. In the event of revocation of anti-dumping duty and owing to significant price undercutting, the domestic industry would be compelled to match its price to that of imports in order to sustain in the market which will lead to company suffering losses.
3. The imports from subject country have remained significant despite anti-dumping duty in force. The price undercutting and price underselling is significant at the landed price without ADD, signifying the likelihood of injury to the domestic industry, should the present duty in force be allowed to cease.
4. The domestic industry has provided the following table with regard to surplus capacities of the subject goods in the subject country. The figures have been substantiated by information available in the web site of respective companies of the subject country.

MBTS Producers	Capacities (in MTA)
Rongcheng Chemical General Factory Co. Ltd.	2400
Ka Shing Chemical Co., Ltd., Shenyang	1000
Tianjin Eastrichon Rubber Additives Co., Ltd.	12000
Nanjing Union Rubber & Chemical Co., Ltd	2400
China Sunsine Chemical Holdings Ltd	7000
Zhengzhou Double Vigour Chemical Product Co. Ltd.	3600
Henan Kailun Chemical Co., Ltd.	3000
Meyors Inc.	1200
Zhenjiang Zhebang Chemical Industry Co. Ltd.	2000
Hebei Smart Chemicals Co., Ltd.	1200
Xinxiang Huarui Fine Chemical Co., Ltd.	10000
Linkwell Rubber Chemical (Hebi) Co., Ltd	1440

Henan Kingway Chemicals	3600
Dalian Richon Chem Co., Ltd.	2400
Qingdao Zhongjian Rubber Chemical Co. Ltd.	15600
Ningbo Actmix Polymer Co., Ltd.	10000
Total known capacities	78840
Consumption	20766
Surplus capacities	58074

(v) The test of injury in a sunset and fresh investigation is different. The legal standards themselves are different. In a fresh investigation, the Designated Authority is required to assess the performance in terms of material injury, threat of material injury or material retardation to the establishment of the domestic industry whereas in a sunset review, the Designated Authority is required to consider the continuation or likelihood of injury. The two are not the same. Likelihood of injury cannot be equated with threat of injury.

Submissions made by ATMA

47. It has contended that based on the facts, there is no case for recurrence of dumping and injury and hence the SSR investigation should be terminated.

Examination by the Authority

48. The Authority notes that none of the exporters / producers of the subject good from the subject country responded to the initiation notification and provided information in the form and manner prescribed. The Authority further notes that the information from IBIS source shows significant price undercutting and price underselling effects of imports of subject goods from the subject country despite the anti dumping duty in place. The Authority notes that there is continued injury from the imports of the product from the subject country during the POI on account of dumping. Thus, there is likelihood of continuation of injury if the anti-dumping duty is allowed to cease, particularly considering the significant dumping margin during POI despite anti-dumping duty in place and given the huge surplus capacities available with the producers/exporters of the subject country.

Magnitude of Injury and Injury margin

49. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of imports from China PR for determination of injury margin during the POI. Thus compared, the injury margin is worked out as under:

Particulars	Unit	China PR
NIP	Rs./Kg	***
Landed Price	Rs./Kg	***
Injury Margin	Rs./Kg	***
Injury Margin	US\$/Kg	***

Causal Link

50. The Authority has examined the submissions with regard to the significance and relevance of causal link in a sunset review investigation. It is important to note under Section 9A(5), the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duty irrespective of whether there have been any imports of the product under consideration during the review investigation period or not. It was examined whether the other parameters listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. It is noted as follows:

Volume and Prices from Other Countries

51. The other country from where the subject goods were substantially imported during the POI is Belgium, as seen from the import statistics. However, it is noted that import price from Belgium is higher than that of the subject country.

Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption

52. It is noted that there is no contraction in demand for the subject product in India. Possible decline in the demand has not, therefore, caused material injury to the domestic industry. Demand of the product in India marked significant increases over the years. There is also no indication of any change in the consumption pattern.

Trade Restrictive Practices of and Competition between the Foreign and Domestic producers

53. The import of the subject product is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic producers compete among one another and at the same time compete with the landed prices of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced substantially by the landed price of subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party even to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

Development of Technology

54. The Authority notes that the technology as also production process for producing the subject product is fairly stabilized with little technical or technological developments. There is no known difference between the technology employed by the petitioner and producers in subject country.

Export Performance

55. The Authority notes that the aforesaid injury analysis has been carried out only in respect of domestic operations of the petitioner and the export performance has not been considered for the purpose.

56. The aforesaid non-attribution analysis indicates that injury to the domestic industry during the POI has not been caused by any other known factor.

Indian industry's interest & other issues

57. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

L. Conclusion

58. The Authority has, after considering the foregoing, comes to the conclusion that:

- (i) The subject goods have been exported to India from the subject country below the normal value despite the anti-dumping duty in place.
- (ii) The domestic industry has suffered material injury;
- (iii) The material injury has been caused by the dumped imports from the subject country and is likely to be caused by continued dumping of subject goods from China PR in case of revocation of duty.
- (iv) The dumped imports and the consequential injury are likely to continue in case of withdrawal of anti-dumping duty, given the significant dumping margin during POI despite the anti-dumping duty in place and given the large volume of surplus capacities available with the subject country.

M. Recommendation

59. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and causal link between dumping and injury to the domestic industry, in terms of the Rules laid down, and having established positive dumping margin in respect of the subject country and a positive determination of likelihood of dumping and injury on account of imports from subject country, and having concluded that the domestic industry suffered material injury, the Authority holds that imposition of definitive anti dumping measure is required in respect of the subject country to prevent injury to the domestic industry. Therefore, Authority considers it necessary to recommend continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country, in the form and manner described hereunder.

60. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the margin of dumping or margin of injury whichever is lesser, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col.8 of the table below is recommended to be

imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

S. No	Sub-Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount (US\$/kg)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	381210 381220 381230 293420 292520	Certain Rubber Chemicals (MBTS) Dibenzothiazole disulphide	China PR	China PR	Any	Any	0.23
2.	- do -	- do -	China PR	Any	Any	Any	0.23
3.	- do -	- do -	Any other than China PR	China PR	Any	Any	0.23

61. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority